जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 356 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मनीष शर्मा की सीधे ही सीडब्ल्युसी के सदस्य व यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में नियुक्ति किसी को पच नहीं रही

ऐसा कहा जा रहा है कि वे राहुल की नवरत्न मीनाक्षी नटराजन के विश्वासी हैं वे उनके घरेलू कामकाज में मदद करते थे

- मनीष शर्मा की इससे पहले पार्टी में कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं हुई थी ना ही उन्हें कोई जिम्मेवारी दी गई थी।
- कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनने के लिए नेताओं को जीवन पर्यंत काम करना होता है और इसकी सदस्यता लंबे कार्यानुभव का नतीजा होता है।
- मीनाक्षी नटराजन की भांति कृष्णा अल्लूवेरा भी राहुल गांधी के इनर ग्रुप, जो अपने आपको जन जगत कहता है, के सदस्य रहे हैं, उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया था और वे यह कह कर गये थे कि वे तेजस्वी यादव के साथ बहुत कड़ाई से पेश आयेंगे और टिकट बंटवारे में तेजस्वी को घुटनों पर ला देंगे।
- पर हुआ उलटा ही, तेजस्वी यादव ने अल्लूवेरा को अपने घर में व बैठकों में भाग लेने तक पर प्रतिबंध लगा दिया और अब नौसिखिए अविनाश पांडे को बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा गया है।

- रेणु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 30 अक्टूबर। कांग्रेस पार्टी में लोग न केवल हैरान हैं बल्कि सदमें में भी है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता दोनों जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, उससे चकित हैं, और राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों को उनकी इच्छाओं और सनकों के हिसाब से काम करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी है। ताजा विवाद मनीष शर्मा की नियुक्ति को लेकर है, जिन्हें हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस की एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया गया है, यह नियुक्ति मीनाक्षी नटराजन के कारण हुई है, जो राहुल गांधी के 'नवरत्नों' में से एक हैं।

मनीष शर्मा नटराजन के घर पर घरेलू सहायक थे (हाँ, आपने सही पढ़ा, घरेलू काम करते थे)। उन्होंने कभी पार्टी में कोई संगठनात्मक पद नहीं संभाला, न ही वे एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, राज्य इकाई, केंद्र या कहीं और कार्यरत रहे हैं। यह उनका पहला आधिकारिक पद है और वह भी सीधे कांग्रेस कार्यसमिति में, पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में, जहाँ नेताओं को जीवनभर के काम और अनुभव के बाद शामिल किया जाता है।

कुछ समय तक शर्मा को पार्टी प्रोजेक्ट्स से जुड़वाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस में कोई औपचारिक पद नहीं मिला था और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, उनके पास कोई ठोस अनुभव नहीं है।

मीनाक्षी नटराजन अब राहुल के करीबी समूह जो खुद को "जन जगत" कहता है, की सदस्य हैं, जो महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेता है। इस समूह के एक अन्य सदस्य कृष्णा अल्लावरू को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उन्हें बिहार का प्रभारी बना दिया गया है।

कांग्रेस का तेजस्वी यादव के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि अल्लावरू ने राहुल गांधी को यह यकीन दिलवाया था कि वह तेजस्वी से सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन इसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप और शी के बीच डील

बुसान, 30 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग के बीच यहां बुसान हवाई अड्डे पर हुई बैठक में चीनी उत्पादों पर अमेरिका में आयात शुल्क 10 प्रतिशत कम करने पर सहमति बन गयी है और बदले में चीन रेअर अर्थ मेटल पर निर्यात नियंत्रण हटाने पर सहमत हो गया है।

ट्रंप ने बैठक के बाद गुरुवार को संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी उत्पादों पर 20 प्रतिशत फेनटेनिल शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा। इससे कुल

- चीन रेअर अर्थ मैटल निर्यात नियंत्रण पर एक साल के लिए हटा देगा और अमेरिका 10 प्रतिशत टैरिफ घटा देगा।

शुल्क 57 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत हो जाएगा।

आधिकारिक सूचना के मुताबिक फिलहाल चीनी उत्पादों पर 55 प्रतिशत शुल्क है जिसमें 20 प्रतिशत फेनटेनिल शुल्क, 25 प्रतिशत आयात शुल्क और 10 प्रतिशत लिबटेशन डे शुल्क है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि शी इस बात पर सहमत हुए हैं कि चीन अमेरिका से सोयाबीन, सोरगम और दूसरे कृषि उत्पाद खरीदेगा। इससे अमेरिकी किसानों को काफी लाभ होगा। साथ ही चीन अमेरिका को रेअर अर्थ मेटल और महत्वपूर्ण खनिजों आदि की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बूसान में हैंड शेक के बाद अमेरिका व चीन ने अजीबो-गरीब समझौता किया

चीन एक साल तक रेयर अर्थ की सप्लाई निर्बाध जारी रखेगा व अमेरिका चीन के निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ नहीं लगाएगा

- भारत में भी सत्तर लाख टन रेयर अर्थ का भंडार है, परन्तु इस खनिज को परिष्कृत कर काम लेने योग्य बनाने की टैक्नॉलजी नहीं है।
- चीन के पास रेयर अर्थ की मोनॉपली नहीं है, पर उसको रिफाइन करने की टैक्नॉलजी पर एकाधिकार है।
- अमेरिका-चीन के हैंड शेक के बाद भारत को कुछ राहत तो है, क्योंकि टाटा, टीसीएस, सुज़लॉन आदि कंपनियों का काम बेधड़क एक साल तक चलेगा, पर इसके बाद क्या होगा, यह चिंता का विषय है।
- क्या भारत साल भर में रेयर अर्थ को रिफाईन करने की टैक्नॉलजी पर महारथ पा सकता है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। भारत के लिए, दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) में डॉनल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुआ दुर्लभ पृथ्वी समझौता राहत भी है और चुनौती भी। इस समझौते में चीन के नए निर्यात नियंत्रणों को एक साल के लिए निलंबित करने के बदले में अमेरिका द्वारा मामूली टैरिफ राहत प्रदान की गई है। यह समझौता भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति की स्थिरता प्रदान करता है। फिर भी, यह एक नाज़ुक स्थिति को उजागर करता है: भारत अब भी उन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रसंस्करण के लिए चीन पर निर्भर है, जो इसके पास प्रचुर मात्रा में हैं।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व में 17 धातुएं हैं, जिनमें नियोडिमियम, डायसप्रोसीयम, और प्रासीडीमियम शामिल हैं। ये आधुनिक जीवन के लिए जरुरी हैं और ईवी मोटर्स, पवन चक्की, स्मार्टफोन और मिसाइल प्रणालियों का संचालन करती हैं। हालांकि ये सच में "दुर्लभ" नहीं हैं, पर इनका शुद्धिकरण जटिल और प्रदूषणकारी होता है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन ने दशकों पहले महारत हासिल की थी। आज, बीजिंग इन तत्वों के प्रसंस्करण का विश्वभर में लगभग 90 प्रतिशत नियंत्रित करता है, जो उसे अप्रतिम भू-राजनीतिक प्रभाव प्रदान करता है।

बुसान समझौता उस प्रभुत्व को केवल विराम देता है। चीन ने एक साल के लिए निर्यातों को जारी रखने पर सहमति दी, जिससे आपूर्ति में व्यवधान के डर को कम किया गया। वॉशिंगटन के लिए यह एक रणनीतिक युद्धिवराम है; बीजिंग के लिए यह एक ऐसा रुख है, जिसका मूल्य बहुत कम है। भारत के लिए, यह राहत इस बात को उजागर करती है कि इसे खनिज संपत्ति को औद्योगिक ताकत में बदलने के लिए अब भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

भारत के समुद्र तटों की रेत में विशाल मोनोजाइट जमा हैं, सात मिलियन टन से अधिक दुर्लभ पृथ्वी तत्व आक्साइड, जो विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं। फिर भी, देश की शोधन क्षमता न्यूनतम है। सरकार के स्वामित्व वाली आई आर ई एल लिमिटेड बुनियादी निष्कर्षण का प्रबंधन करती है, लेकिन उच्च-शुद्धता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव को लहर विहीन चुनाव माना जा रहा है, अतः विद्रोही उम्मीदवार खूब पनप रहे हैं

वैसे हर चुनाव में विद्रोही उम्मीदवार सरदर्द बनते हैं, पार्टियों के लिए, पर इस बार कुछ फर्क है

- जदयू, आरजेडी व भाजपा गठबंधनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अतः विद्रोही उम्मीदवारों की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
- यह तथ्य स्वीकार करते हुए सभी पार्टियों ने विद्रोही उम्मीदवारों को पार्टी से निकालने का रास्ता अपनाया है।
- जदयू अब तक सोलह नेताओं को निकाल चुका है, पार्टी से। भाजपा लगभग बीस, आरजेडी सत्ताइस वरिष्ठ नेताओं की पार्टी सदस्यता खत्म कर चुकी है। इन नेताओं में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक भी शामिल हैं।
- कांग्रेस ने यह रास्ता नहीं अपनाया है, पर, असंतोष चरम पर है। हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर दो प्रतिद्वंदी धड़े भिड़ गए, लाठी-भाटा जंग भी हुआ।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। सर्वेक्षणों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाए जाने के साथ ही, बिहार में एक दिलचस्प सवाल महत्वपूर्ण बन गया है कि "बागी" प्रत्याशी संबंधित राजनीतिक गठबंधनों के की संभावनों बनायेंगे या बिगाड़ेंगे।

विद्रोही ज्यादातर वे हैं, जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। ऐसे लोग पहले भी अपने-अपने दलों के लिए सिरदर्द साबित हुए हैं। इस बार फर्क यह है कि टिकट वितरण में असंतोष के कारण, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को कई नेताओं, जिनमें वरिष्ठ विधायक भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई नियुक्त

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर। न्यायमूर्ति सूर्य कांत को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरूवार को एक

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। मौजूदा सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे है और जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को शपथ लेंगे।

सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति सूय कांत 24 नवम्बर को पद की शपथ लेंगे। वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का स्थान लेंगे जो 23 नवम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने कुछ ही दिन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विश्व में तीसरे शीत युद्ध की तैयारी शुरु हो गई है?

ट्रंप ने पुनः न्यूक्लियर टैस्टिंग की शुरुआत करने की घोषणा की

- उनका तर्क था कि न्यूक्लियर टैस्टिंग करके वे न्यूक्लियर बम बनाएंगे, जिससे वे अन्य देशों, रूस व चीन से, न्यूक्लियर बम की संख्या में पीछे न रह जाएं।
- रूस ने 1990 से, अमेरिका ने 1992 व चीन ने 1996 में न्यूक्लियर संधि की पालना करते हुए न्यूक्लियर टैस्टिंग बंद कर दी थी।
- अमेरिका व रूस दोनों देशों के पास 1550 न्यूक्लियर बम हैं। चीन के पास लगभग एक हजार और अब नए खिलाड़ी भी आ गए हैं, जैसे भारत, पाक, नॉर्थ कोरिया, इज़रायल। अतः शीत युद्ध के बाद पुनः यह प्रतिस्पर्धा शुरु होना खतरे की घंटी है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया एक बार फिर अनजाने में उस दौर की ओर बढ़ रही है, जहाँ परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है।

परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच फिर से परीक्षण शुरू करने और अपने भंडार बढ़ाने की होड़ मच गई है। इससे लगता है कि शीत युद्ध की सोच फिर लौट आई है

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने आज घोषणा की कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा, रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों की बराबरी करने के लिए।

यह कदम तीनों परमाणु महाशक्तियों, अमेरिका, रूस और चीन के बीच नए सिरे से प्रतिस्पर्धा शुरू कर सकता है, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु भंडार हैं।

यह एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि इससे 1990 के दशक में बनी वह पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बिखर जाती है, जो परमाणु हथियारों के भंडारण और प्रयोग को नियंत्रित करती थी।

इस कदम की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक किसी बड़े परमाणु देश ने वास्तविक परमाणु परीक्षण नहीं किया था, रूस ने 1990 के बाद, अमेरिका ने 1992 के बाद और चीन ने 1996 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया।

आज अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण फिर शुरू करने की घोषणा दरअसल रूस द्वारा हाल ही में किए गए उन्नत परमाणु हथियार परीक्षणों का जवाब है। रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में आई कड़वाहट के बाद यह स्थिति बनी है। इस बीच चीन भी चुपचाप अपनी परमाणु क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है।
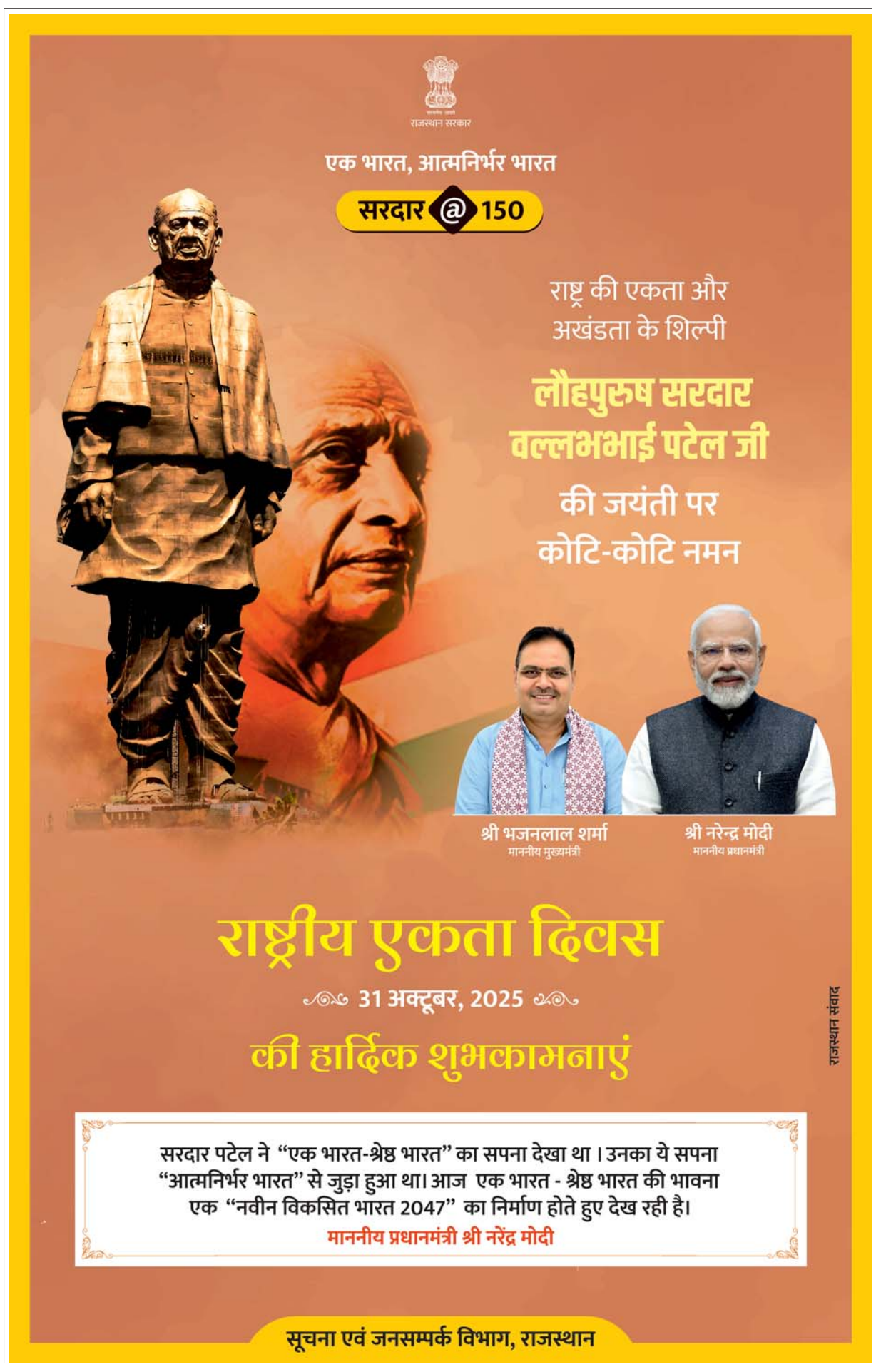
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)